बीएसएनएल का मोबाइल टावर कारोबार होगा अलग

नई दिल्ली,13 सितम्बर (ए)। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड के मोबाइल टावर इंफ्रास्ट्रक्चर को अलग करते हुए इसे कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली एक अलग कम्पनी के हवाले करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की आज यहां हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। इस मंजूरी से बी.एस.एन.एल. एक अलग सहायक कंपनी बनाकर अपने टावर इंफ्रास्ट्रक्चर का मुद्रीकरण कर सकेगी। देश में लगभग 4,42,000 मोबाइल टावर हैं जिनमें से 66,000 से अधिक मोबाइल टावर बी.एस.एन.एल. के हैं। बी.एस.एन.एल. की एक स्वतंत्र, समर्पित टावर कंपनी की केंद्रित पहुंच से टावर किराए में वृद्धि होने के साथ-साथ नई कम्पनी के लिए अधिक धन अर्जित होगा। देश में दूरसंचार टावर उद्योग टैलीकॉम कंपनियों के लिए बुनियादी सुविधा प्रदाता के रूप में एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में उभरा है।

फर्जी कंपनियों के 1 लाख डायरेक्टर्स होंगे अयोग्य

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (ए)। केंद्र सरकार ब्लैक मनी से निपटने के लिए लगातार प्रहार कर रही है। इन्हीं कदमों के तहत सरकार ने फैसला किया है कि फर्जी कंपनियों से जुड़े करीब 1.06 लाख डायरैक्टर्स को अयोग्य करार दिया जाएगा। कंपनी मामलों के मंत्रालय ने 2.09 लाख कंपनियों द्वारा लंबे समय से कारोबारी गतिविधि नहीं करने के कारण उनके पंजीकरण को रद्द कर दिया था। इस कदम के बाद सरकार ने यह नया फैसला किया है। इसके अलावा बैंकों को इन कंपनियों के बैंक अकाऊंट्स पर भी रोक लगाने का आदेश दिया गया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि मंत्रालय ने 1,06,578 डायरैक्टर्स की पहचान की है, इनको कंपनी एक्ट 2013 के सैक्शन 164 (2) के तहत अयोग्य ठहराया जा सकेगा। सैक्शन 164 के तहत किसी कम्पनी का कोई डायरैक्टर जो लगातार 3 वित्त वर्ष तक कंपनी की फाइनैंशियल स्टेटमैंट्स या वार्षिक रिटर्न नहीं भरता है तो उसे किसी कंपनी में या फर्म में अगले 5 साल तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है। कंपनी मंत्रालय 2.09 लाख कंपनियों के डाटा की अभी जांच कर रहा है।

प्याज की जमाखोरी पर सरकार सख्त व्यापारियों के खिलाफ जांच के निर्देश

नई दिल्ली, 13 सितम्बर (ए)। सरकार ने प्याज की जमाखोरी करके सुनियोजित तरीके से उसकी कीमतें बढ़ाने के मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए महाराष्ट्र के 5 बड़े व्यापारियों के खिलाफ जांच कर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार उपभोक्ता मामलों के सचिव अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने महाराष्ट्र के मुख्य सचिव को पत्र भेजकर कहा कि लासलगांव और पिंपलगांव के 5 बड़े व्यापारियों ने पिछले दिनों सुनियोजित तरीके से बाजार में प्याज की कीमतें बढ़ाने के लिए इसकी भारी जमाखोरी की। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से इन व्यापारियों के खिलाफ जांच करवाने और आवश्यक कार्रवाई करने को कहा है।

सूत्रों के अनुसार इसके पहले खुफिया विभाग ने इन व्यापारियों के खिलाफ रिपोर्ट दी थी। उल्लेखनीय है कि हाल में राष्ट्रीय राजधानी और देश के कई हिस्सों में प्याज की कीमत 35 से 40 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई थी। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्याज के मूल्य नियंत्रित करने के लिए नेफेड और एस.ए.एफ.सी. को एक हजार टन प्याज खरीदने को कहा था। सरकार ने राज्यों से भंडारण सीमा तय करने तथा जमाखोरी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की भी सलाह दी थी।

सट्टेबाजी से बढ़ी कीमतें: सरकार का मानना है कि सट्टेबाजी और अवांछित व्यापारिक गतिविधियों के कारण प्याज की कीमतें बढ़ी हैं। विभागीय स्तर पर नियमित रूप से इसकी समीक्षा की जा रही है। केन्द्र ने प्याज की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए 11,400 टन प्याज के आयात की अनुमति भी दी थी। इसमें से 2400 टन प्याज आ गया है तथा 9000 टन और आने वाला है। वर्ष 2016-17 के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार प्याज का उत्पादन 2 करोड़ 17 लाख टन होने की उम्मीद है जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गुजरात और बिहार प्रमुख प्याज उत्पादक राज्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिया जेपी ग्रुप को एक और झटका

नई दिल्ली,13 सितम्बर (ए)। सुप्रीम कोर्ट ने जेपी ग्रुप को एक और झटका दे दिया है। कोर्ट ने जेपी को उसके कैलिप्सो कोर्ट प्रॉजेक्ट के 10 फ्लैट बायर्स को पजेशन देने में देरी के लिए 50-50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया। जेपी का कैलिप्सो कोर्ट प्रॉजेक्ट नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर स्थित नोएडा सेक्टर 128 में स्थित है।

पिछले साल जुलाई महीने में सुप्रीम कोर्ट ने ही नैशनल कन्ज्यूमर डिस्प्यूट रीड्रेसल कमिशन (एनसीआरडीसी. के उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें पजेशन देने में देरी पर सालाना 12 प्रतिशत का जुर्माना देने को कहा गया था। तब देश की सर्वोच्च अदालत ने जेपी को 3 अगस्त 2016 तक 4 करोड़ रुपए जमा कराने का आदेश दिया था। ऐसा नहीं करने पर जेपी को 12 प्रतिशत जुर्माना भरने का एन.सी.आर.डी.सी. का आदेश लागू होने की बात कही गई। गौरतलब है कि जेपी ग्रुप इन दिनों बेहद मुश्किल हालात से गुजर रहा है।

उसके 30,000 फ्लैट बायर्स ने मोर्चा खोल रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को इस मामले में जेपी को 27 अक्टूबर तक न्यायालय की रजिस्ट्री में दो हजार करोड़ रुपए जमा कराने का निर्देश दिया। इसके साथ ही न्यायालय ने नैशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल की ओर से अंतरिम समाधान की व्यवस्था के रूप में नियुक्त प्रफेशनल आईआरपी को इसका प्रबंधन अपने हाथ में लेने और खरीददारों तथा कर्जदाताओं के हितों के संरक्षण की योजना तैयार करने का भी निर्देश दिया।

ज्यादा कीमत वसूलने वालों की होगी निगरानी

नई दिल्ली,13 सितम्बर (ए)। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान ने अधिकारियों को एमआरपी से अधिक कीमत वसूलने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। पासवान ने अधिकतम खुदरा कीमत (एमआरपी) से अधिक मूल्य पर सामान बेचने तथा जबरन सर्विस चार्ज वसूलने के मामलों के बारे में सरकार को सूचित करने के साथ-साथ जनता को जागरूक बनाने के लिए उपभोक्ता संगठनों का आह्वान किया है। पासवान ने इस संबंध कई ट्वीट किए हैं। एक ट्वीट में उन्होंने कहा है कि 'एमआरपी से अधिक कीमत वसूल किए जाने के मामलों पर निगरानी रखने के लिए सभी राज्यों के लीगल मेट्रोलॉजी (मापतौल) अधिकारियों को निर्देश दिया गया है।

महंगाई बढ़ने के बावजूद सेंसेक्स में तेजी का रुख बरकरार

मुंबई,13 सितंबर । खुदरा महंगाई के पांच महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच जाने के बावजूद घरेलू संस्थागत निवेशकों की लिवाली से सेंसेक्स में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी देखी गई. बंबई शेयर बाजार का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सुबह 57.08 अंक यानी 0.17 प्रतिशत की तेजी के साथ 32,215.74 अंक पर कारोबार रहा था. इसे पावर, टिकाऊ उपभोक्ता उत्पाद, तेल एवं गैस, आईटी और पीएसयू समूह की कंपनियों की तेजी से भी बल मिला. पिछले चार लगातार कारोबारी दिवसों से सेंसेक्स में तेजी बनी हुई है. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 8.25 अंक की बढ़त लेकर 10,101.30 अंक पर कारोबार कर रहा था.

सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, डॉ रेड्डीज, अदानी पोर्ट्स, सन फार्मा, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, कोल इंडिया, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई, बजाज ऑटो, ओएनजीसी और मारुति सुजुकी के शेयरों में 2.21 प्रतिशत तक की तेजी रही.

ब्रोकरों ने बताया कि अगस्त में खुदरा महंगाई के पांच महीने के उच्चतम स्तर 3.36 प्रतिशत पर पहुंच जाने के बाद भी बाजार की धारणा मजबूत बनी रही.

कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ लॉन्च एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए 120 करोड़ रुपए

नई दिल्ली,13 सितम्बर (ए)। कंस्ट्रक्शन कंपनी कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ आज से खुल गया है। आईपीओ 15 सितंबर को बंद होगा। इसका प्राइस बैंड 245-250 रुपए रखा गया है। जबकि लॉट साइज 60 शेयर रखा गया है। इस आईपीओ से कंपनी की 400 करोड़ जुटाने की योजना है।

120 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से जुटाए: कंपनी ने मंगलवार को एंकर इन्वेस्टर्स से 120 करोड़ रुपए जुटाए हैं। गोल्डमैन सैच इंडिया लिमिटेड, रिलायंस कैपिटल ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ग्रोथ फंड सहित कुल 15 एंकर इन्वेस्टर्स हैं।

कंपनी का बिजनेस मॉड्यूल: कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल, कमर्शियल बिल्डिंग बनाने का कारोबार करती है। कंपनी रियल एस्टेट डेवलपर्स के लिए काम करती है। इसके क्लाइंट्स में लोधा ग्रुप, रुस्तमजी, गोदरेज प्रॉपर्टीज शामिल हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स, ओबेरॉय कंस्ट्रक्शन भी कंपनी के क्लाइंट्स हैं। एसएमसी इन्वेस्टमेंट्स एंड एडवाइजर्स लिमिटेड के रिसर्च हेड सचिन सर्वदे के मुताबिक, कैपेसाइट इंफ्राप्रोजेक्ट्स का आईपीओ अच्छा। वैल्युएशन अच्छा होने से इसमें निवेश किया जा सकता है।

800 सीसी इंजन के साथ भारत में लांच हो सकती है डुकाटी

स्क्रैम्बलर Mach 2.0

जालंधर ,13 सितम्बर (ए)। इटली की ऑटोमेकर कंपनी डुकाटी अपनी नई बाइक स्क्रैम्बलर Mach 2.0 को भारत में जल्द लांच करने की योजना बना रही है। रिर्पोट मुताबिक, डुकाटी की महंगी बाइक्स में से यह एक होगी। भारत में इसकी कीमत कीमत 8.60 लाख रुपए के आस-पास रह सकती है। रिर्पोट के अनुसार, भारत में इस बाइक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। कंपनी इस बाइक को भारत में कब लांच करेगी इसकी सटीक जानकारी तो नहीं है लेकिन जनकारों की माने तो कंपनी इसे अगले कुछ महीनो के भीतर लांच कर सकती है। इंजन की बात करें तो नई डुकाटी स्क्रैम्बलर Mach 2.0 में 803cc का एयर कूल्ड L-twin इंजन लगा होगा। जोकि 73bhp की पावर और 67Nm का टार्क जनरेट करता है।

जन धन योजना के तहत खुले तीस करोड़ बैंक खाते: जेटली

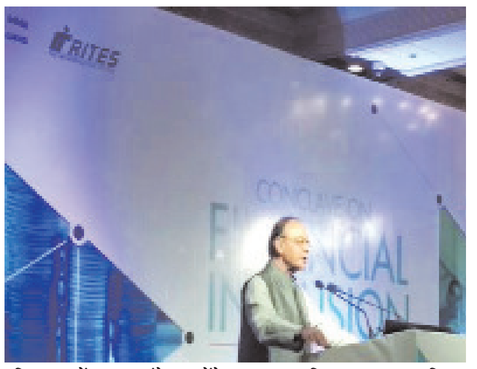

नई दिल्ली,13 सितम्बर (ए)। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने यूनाइटेड नेशंस के फाइनेंशियल इन्क्लूजन कॉन्क्लेव में बोलते हुए कहा कि पिछले तीन साल में जन धन योजना के तहत 30 करोड़ परिवारों के बैंक खाते खोले गए हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना की शुरुआत से पहले करीब 42 प्रतिशत परिवार बैंक सेवा से जुड़े हुए नहीं थे। जन धन योजना बैंक खाते खोलने की देश की सबसे बड़ी मुहिम है। इसका लक्ष्य सभी व्यावसायिक बैंकों में जीरो बैलेंस अकाउंट खोलकर प्रत्येक परिवार को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ना था।

बताया नोटबंदी का फायदा: जेटली ने कहा कि जीरो बैलेंस अकाउंट का अनुपात 77 प्रतिशत से कम होकर 20 प्रतिशत रह गया है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण सुविधा का विस्तार होने से ये बैंक खाते भी परिचालन में आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजना की शुरुआत के तीन महीने बाद सितंबर 2014 में 76.81 प्रतिशत खातों में जमा राशि शून्य थी। अब इस तरह के खाते कम होकर 20 प्रतिशत रह गए हैं। उन्होंने जन धन योजना को श्रेय देते हुए कहा कि अब 99.99 प्रतिशत परिवारों के पास कम से कम एक बैंक खाता हैं। नोटबंदी का फायदा गिनाते हुए जेटली ने कहा कि नोटबंदी से टैक्स बेस बढ़ा है। कैश कम हुआ है और इकोनॉमी अधिक फॉर्मल हुई है।

एसके टेलिकॉम के साथ एयरटेल ने की खास डील

नई दिल्ली,13 सितम्बर (ए)। देश की दिग्गज दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनी भारती एयरटेल ने दक्षिण कोरिया की एसके टेलिकॉम के साथ एक डील की है। इस डील के तहत एयरटेल भारत में सबसे ज्यादा टेलिकॉम नेटवर्क बनाने के लिए एसके टेलीकॉम की दक्षता का फायदा उठाएगी। सुनील मित्तल की कंपनी का कहना है कि दोनों कंपनियां साझेदारी में कई सेक्टर्स में काम करेंगी। इनमें नेटवर्क अनुभव में सुधार के लिए विशेष सॉफ्टवेयर विकसित करना, मशीन सीखने समेत उच्च डिजिटल उपकरण का लाभ लेना, बिग डेटा और प्रत्येक ग्राहक के डिवाइस अनुभव के आधार पर नेटवर्क प्लानिंग में सुधार करने के लिए कस्टम उपकरण का निर्माण करना शामिल है। भारती एयरटेल चेयरमैन सुनील मित्तल ने कहा, यह दोनों कंपनियां 5जी, नेटवर्क फंक्शन्स वर्चुअलाइजेशन , सॉफ्टवेयर-डिफाइंड नेटवर्किंग और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए कुछ स्टैंडर्ड को विकसित करने के लिए काम करेगीं। साथ ही भारतीय यूजर्स को ध्यान में रखते हुए इन तकनीकों को लागू करने के लिए एक सक्षम इकोसिस्टम (पारिस्थितिकी तंत्र) बनाने के लिए संयुक्त रूप से काम किया जाएगा।

चीन में एप्पल के आईफोन-8 की चमक रह सकती है फीकी !

पेइचिंग,13 सितम्बर (ए)। एप्पल की तरफ से लांच किए गए आईफोन-8 की चीन में चमक फीकी रह सकती है। चीन में 8 शुभ अंक माने जाने पर दुनिया की सबसे बड़ी स्मार्टफोन मार्कीट में एप्पल को खासी जद्दोजहद का सामना करना पड़ सकता है। एप्पल के आईफोन 8 की 1000 डालर कीमत आईफोन-7 पल्स के मुकाबले ज्यादा है, जिसके साथ अमरीका में इसकी बिक्री कम लगने की संभावना है जबकि चीन में इसका प्रभाव भी कम रहेगा।

चीन में एप्पल के अगले आईफोन की कपरटीनो आधारत फर्म के लिए सफलता बहुत महत्वपूर्ण है, जिसने चीन में स्थायीय प्रतिद्वंदी कंपनियां हवाई प्रौद्यौगिकी कंपनी लिमिटेड, ओपो, वीवो और जियोमी की पेशकशों में पीछे लुढ़क कर 5वें स्थान पर आ गई है।

एप्पल की बिक्री में 10 प्रतिशत गिरावट आई : ग्रेटर चाइना की ताइवान और हांगकांग ने जुलाई की खत्म तिमाही में दोगुनी आईफोन की बिक्री 18 प्रतिशत दर्ज की गई जिसके साथ कंपनी अमरीका और यूरोप के बाद टॉप पर पहुंची थी जबकि दूसरी ओर सभी क्षेत्रों के मुकाबले में में इसकी बिक्री में 10 प्रतिशत गिरावट आई है। कंसलटैंसी काऊंटर प्वाइंट रिसर्च से प्राप्त आंकड़ों ने चीन के स्मार्टफोन के 2015 में जनवरी-जून में आईफोन के हिस्से में 14 से 9 प्रतिशत शिपमैंट में गिरावट दिखाई थी। जबकि 2014 में चीन में आईफोन -6 को बहुत कम रिस्पांस मिला था।

उधार की किश्तों में खरीदो: चीन में एप्पल के सब से महंगे फोन का प्रभाव किश्तों में बिक्री करने का बहुत ज़्यादा होगा। वांगयांग जो पेइचिंग में सबसे बड़े बाजार में फोन स्टोर चलाते है, ने बताया कि इस समय ऑनलाइन खरीददारी बहुत ज्यादा होने की आशा है क्योंकि ग्राहक किश्तों में अदायगी करना चाहते हैं। एप्पल कंपनी खुद चीन में किश्तों पर 3 स्टेट ड्क्षलकड बैंकों की सहायता के साथ बिक्री करने की योजना बना रही है।

अब विदेश से नहीं मंगवा सकेंगे खिलौने, सरकार ने सख्त किए नियम

नई दिल्ली,13 सितम्बर (ए)। सरकार ने विदेश से खिलौने इंपोर्ट करवाने के नियमों को सख्त कर दिया है। देशी खिलौना उत्पादकों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड की तरफ से 1 सितंबर को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार केवल वो ही खिलौने अब इंपोर्ट हो सकेंगे जो भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) के तय मानकों पर खरे उतरेंगे।

कड़े किए गए नियम: इलेक्ट्रिक टॉय, स्लाइड्स, झूले और एक्टिविटी वाले टॉयज के इंपोर्ट पर सख्ती की गई है। अधिसूचना के अनुसार खिलौनों की फीजिकल व मेकेनिकल प्रॉपर्टी, केमिकल कांटेट, ज्वलनशीलता और टेस्टिंग पर नए मानक तय किए गए हैं। जो भी खिलौना इन मानकों पर खरा उतरेगा, केवल उसी को देश भर में बेचने की अनुमति प्रदान की जाएगी। कंपनियों या फिर इंपोर्टर को ऐसे खिलौनों के लिए स्वतंत्र लैबोट्री से सर्टिफिकेट भी लेना होगा।

70%खिलौने चीन से इंपोर्ट

फेस्टिव सीजन के शुरु होने से पहले सरकार के इस कदम से खिलौना बेचने वालों में मायूसी छा गई है। ज्यादतर दुकानदारों ने चीन से खिलौने मंगाने का ऑर्डर दे रखा है, जिसकी कीमत 5 हजार करोड़ रुपए से ज्यादा है। बता दें कि देश में इस वक्त 70 फीसदी से अधिक खिलौने चीन से इंपोर्ट होते हैं। सरकार को इन पर कस्टम ड्यूटी भी मिलती थी। लेकिन सरकार बच्चों की सेहत से किसी तरह का समझौता नहीं कर सकती है।